www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क : ₹ 350

सत्यमेव जयते

रोज़गार समाचार

सभी को अवसर
OPPORTUNITIES FOR ALL

साप्ताहिक

खण्ड 37 अंक 50 पृष्ठ 96 | नई दिल्ली 16-22 मार्च 2013 | ₹ 8.00

रोज़गार सारांश

सं.लो.से.आ.

● संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा-2013 और भारतीय वन सेवा परीक्षा-2013 अधिसूचित

अंतिम तिथि: 04.04.2013

क.च.आ.

● कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उपनिरीक्षक एवं के.औ.सु.ब. में सहायक उप निरीक्षक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आसूचना अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए एक अखिल भारतीय परीक्षा आयोजित

अनुमानित रिक्तियां: 2240

अंतिम तिथि: 12.04.2013

मंत्रिमण्डल सचिवालय

● मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा लगभग 279 अनुसंधान अधिकारी, निजी सहायक और आशुलिपिकों की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित आवश्यकता

अंतिम तिथि: 17.04.2013

आयुध निर्माणी

● आयुध निर्माणी, कानपुर को 100 श्रमिकों (अर्द्ध कुशल) की आवश्यकता

अंतिम तिथि: प्रकाशन की तिथि से 21 दिन

इंडियन ऑयल

● इंडियन ऑयल द्वारा 61 कनीय इंजीनियरिंग सहायक-IV, कनीय क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट-IV/प्रशिक्षु, कनीय मैटेरियल सहायक-IV, प्रशिक्षु आदि की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित

अंतिम तिथि : 31.03.2013

बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सशस्त्र सेनाओं, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों की अन्य रिक्तियों के लिए अंदर के पृष्ठ देखें.

महत्वपूर्ण

संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2013 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2013 अधिसूचित कर दी हैं. दोनों परीक्षाओं की पद्धति में व्यापक परिवर्तन किये गये हैं.

रोज़गार समाचार 23.03.2013 के अंक से नई पद्धति पर लेख प्रकाशित करना शुरू करेगा. ये आलेख इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के होंगे.

इन परीक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को इन लेखों से काफी लाभ होगा.

रक्षा ख़रीद प्रक्रिया को राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्य से जोड़ें

-भरत वर्मा

भविष्य में किसी भी संघर्ष की स्थिति में भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति तथा देश की सैन्य क्षमता कुछ ऐसी होनी चाहिए कि चीन और पाकिस्तान अरुणाचल तथा कश्मीर के लिए ख़तरा होने की बजाए क्रमशः तिब्बत और लाहौर का बचाव करने के लिए मज़बूर हो जाएं. ये क्षमताएं उनमें एक प्रभावकारी डर पैदा करने का काम करेंगी.

लेकिन, वर्तमान रक्षा ख़रीद प्रणाली, निर्णय लेने में तालमेल की कमी, भ्रष्टाचार के उच्चतम स्तर के साथ, भारत के लिए उत्पन्न अत्यधिक ख़तरों के अनुरूप सशस्त्र सेनाओं के लिए सैन्य क्षमताओं का निर्माण करना, बेहद कठिन काम है. इन ख़तरों में पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन की तरफ से हमारे ऊपर दो तरफा मोर्चों पर थोपा गया युद्ध शामिल है. दोनों देश एक बड़े भारतीय भू-भाग पर अपना दावा ठोकते रहते हैं. इसके अलावा देश के 40 प्रतिशत से अधिक भू-भाग पर माओवादियों का प्रभाव होने के कारण बड़ी मात्रा में सैन्य संपत्तियों को भर आंशिक युद्धक स्थिति ही निगल जाती है.

दशकों से सरकार की उपेक्षा के कारण भारतीय सैन्य शक्ति क्षीण हुई है और इसकी क्षमताएं सिकुड़ रही हैं. वस्तुओं की सूची में शामिल उपकरण पुराने और संग्रहालय में रखने जैसी स्थिति में हैं. इन सब के बावजूद सेना से देश की सीमाओं की सफलतापूर्वक रक्षा करने की आशा की जाती है. नई दिल्ली की ओर से दशकों से अपनी सेना की इस तरह उपेक्षा भले ही धीरे-धीरे हुई हो, लेकिन सरकार के इस आखिरी उपकरण का मनोबल गिरकर निचले स्तर पर पहुंच गया है. दुःखद बात ये है कि वित्त मंत्रालय की ओर से हाल में लागू रू 10,000/-करोड़ की बजटीय कटौती का, बेहद ज़रूरी सैन्य आधुनिकीकरण कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. भारतीय वित्त मंत्रालय के इस कदम से जहां चीन और पाकिस्तान की हिम्मत निश्चित तौर पर बढ़ेगी वहीं भारतीय सेना के मनोबल में कमी आई है. रक्षा के लिए कम बजटीय आबंटन और खरीद प्रक्रिया में नौकरशाहों की लालफीताशाही ने रक्षा सेवाओं को तंग हालत में पहुंचा दिया है. उपकरणों और मानव संसाधन की इस खराब स्थिति में सशस्त्र बलों का मनोबल गिरना कोई आश्चर्य की बात नहीं है. आज भारत चीन के खतरे से निपटने अथवा यदि अफगानिस्तान से पश्चिमी देशों की सेनाओं की वापसी के बाद उसके लिए ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है, दो तरफा युद्धक माहौल से निपटने के लिए तैयार नहीं दिखता है.

कटु सत्य ये है कि यदि भारतीय सेना सीमाओं की सुरक्षा करने में असमर्थ है तो फिर भारत का विखंडन होने में भी कुछ देर नहीं लगेगी. एक अन्य चिंताजनक कारण ये है कि पुलिस और केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल माओवादियों के हमलों से सफलतापूर्वक नहीं निपट सकते. दुर्भाग्यवश देर सवेर सेना को ही माओवादियों के खिलाफ अभियानों को अपने हाथ में लेने के लिए बुलाना पड़ेगा. चीन और पाकिस्तान भी यही सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारतीय सेना को सीमाओं से हटाकर देश में बढ़ते आंतरिक विद्रोह से निपटने के लिए लगा दिया जाए. इससे सेना और ज़्यादा तनाव में आ जाएगी, जो पहले से ही राजनीतिक नेतृत्व की कठोर उदासीनता के चलते अपनी घटती क्षमताओं को लेकर खासे दबाव में है.

इसके अलावा कोई भी सेना तब तक अतिरिक्त जोश नहीं दिखा सकती जब तक कि मानव संसाधानों के अलावा उसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस न किया जाए. साथ ही कोई राष्ट्र तब तक महाशक्ति नहीं बन सकता जब तक उसका एक बड़ा रक्षा औद्योगिक परिसर नहीं होगा. भारत का दुनिया में रक्षा उपकरणों के सबसे बड़े आयातकों में से एक होने का जो कारण है उसके पीछे की सच्चाई इस बात को लेकर है कि 'आत्म-पर्याप्तता' मंत्र के परिवेश में यहां देश के दुर्लभ और मूल्यवान संसाधनों को रक्षा विभाग की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की अदक्षता की वजह से व्यर्थ में गंवा दिया गया है. स्कॉर्पिन पनडुब्बी के उत्पादन में हुई देरी के पीछे मुख्य कारणों में से एक तथ्य ये था कि फ्रांस के डीसीएनएस ने सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड मझगांव डाक के उन्नयन और आधुनिकीकरण में बहुत अधिक प्रयास करने पड़े.

आज सशस्त्र बलों के पास जो युद्धक उपकरण हैं वे बहुत ही ख़राब हालत में हैं और सरकारी रक्षा उद्योग इससे निपटने की स्थिति में भी नहीं है. रक्षा सेनाओं को सुसज्जित करने का एकमात्र उपाय है कि सरकारी रक्षा इकाइयों का निजीकरण किया जाए, इन्हें टियर-1 सप्लायर के तौर पर निजी क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाए, डीआरडीओ को केवल अति महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास तक सीमित किया जाए, न्यूनतम 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ भारतीय और पश्चिमी रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग और संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाए. इससे आने वाले दशकों में भारत में एक व्यापक और आधुनिक रक्षा औद्योगिक परिसर तैयार हो सकेगा, जिससे न केवल भारतीय सेनाएं साजो सामान से लैस हो पाएंगी, बल्कि निर्यात के जरिए देश को राजस्व की भी प्राप्ति होगी.

(शेष पृष्ठ 95 पर)

अर्थव्यवस्था की स्थिति और बजट 2013-14

-बिबेक देबराय

देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण से प्रारंभ की जा सकती है. इसके शुरू में कहा गया है कि ''भारत की आर्थिक मंदी आंशिक रूप से बाहरी कारणों पर आधारित रही है, लेकिन इसके घरेलू कारण भी महत्वपूर्ण हैं. वित्तीय संकट के बाद किए गए सुदृढ़ उपायों की बदौलत 2009-10 और 2010-11 में विकास में मजबूती आई'' इस संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि के आंकड़े इस प्रकार हैं: 2009-10 में 8.6, 2010-11 में 9.3, 2011-12 में 6.2 और 2012-13 में 5.0 प्रतिशत. उल्लेखनीय है कि केंद्रीय नमूना संगठन (सीएसओ) द्वारा 2012-13 में विकास दर के बारे में व्यक्त किए गए 5.00 प्रतिशत के अनुमान को कोई चुनौती नहीं दी गई है. प्रश्न यह है कि 2011-12 और 2012-13 में विकास दर धीमी क्यों रही? सर्वेक्षण के अनुसार ''ब्याज दरें ऊंची रहने और नीतिगत दबावों के कारण ऐसा हुआ''. बाद में हमें बताया गया कि ''अनेक घटक जिम्मेदार हैं. पहला यह है कि संकट के बाद मांग बढ़ाने के लिए किए गए मौद्रिक और राजकोषीय उपाय अत्यंत व्यापक थे.... नतीजतन मुद्रास्फीति बढ़ी और सुदृढ़ मौद्रिक उपायों से भी खपत की मांग में कमी आई.

दूसरे, निवेश संबंधी अड़चनों और कड़ी मुद्रा नीति के फलस्वरूप 2011-12 से कार्पोरेट और ढांचागत निवेश दोनों में कमी आने की शुरुआत हुई. जिस समय आर्थिक मंदी जारी थी, उसे दो अतिरिक्त आघात लगेः वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी को यूरो क्षेत्र में संकट और अमरीका में राजकोषीय नीति को लेकर अनिश्चितता और कमजोर मानसून (कम से कम प्रारंभिक चरण के दौरान) से आघात पहुंचा. सर्वेक्षण में आगे कहा गया है कि ''कार्पोरेट निवेश में कमी आने का एक तीसरा संभावित कारण नीतिगत अड़चनें (जैसे पर्यावरण संबंधी मंजूरियां प्राप्त करना, ईंधन संबंधी कारण, अथवा भूमि अधिग्रहण कार्य) थीं, जिनकी वजह से अनेक बड़ी परियोजनाएं अटक गईं, जिनकी वजह से नए निवेश में बाधाएं आईं.

बजट भाषण में कहा गया है कि विकास दर में फिर से बढ़ोत्तरी लाना और खपत व्यय तथा निजी निवेश दोनों को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है. लेकिन बजट से ऐसी उम्मीद करना युक्तिसंगत नहीं है. यह केवल एक दस्तावेज है. 2013-14 के बजट आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद में 13.4 प्रतिशत की अनुमानित बढ़ोत्तरी पर आधारित हैं. यही बजट भाषण में कहा गया है, ''चालू वर्ष के दौरान सीएसओ ने 5 प्रतिशत और रिजर्व बैंक ने 5.5 प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान लगाया है.'' ऊपर वर्णित बातों के अलावा आर्थिक सर्वेक्षण में भी यही कहा गया है कि ''भारत में सकल घरेलू उत्पाद की तिमाही वृद्धि दर 2010-11 की चौथी तिमाही और 2011-12 की चौथी तिमाही के बीच प्रत्येक तिमाही में निरंतर गिरती गई है. चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही में विकास दर 5.4 प्रतिशत आंकी गई, जबकि सीएसओ ने अग्रिम अनुमान में 2012-13 के लिए विकास दर 5 प्रतिशत रहने की बात कही थी.'' इसलिए 2012-13 के पिछले 6 महीनों में अर्थव्यवस्था का विकास 4.6 प्रतिशत रहा है. हां, आर्थिक सर्वेक्षण में 2013-14 में विकास दर 6.1 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना व्यक्त की गई है. सर्वेक्षण में इस मंदी के कारणों की पहचान की गई है लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि इस प्रवृत्ति में बदलाव कैसे आएगा और विकास दर 4.6 प्रतिशत से बढ़ कर 6.1 प्रतिशत से 6.7 प्रतिशत के बीच कैसे पहुंचेगी या सर्वेक्षण में हाल के जिन उपायों का उल्लेख किया गया है क्या वे पूरी तरह संतोषजनक हैं. दलील यह नहीं है कि विकास दर 4.6 प्रतिशत पर बनी रहेगी, संभव है इसमें बढ़ोतरी हो, लेकिन यह बढ़ कर 5.5 प्रतिशत, संभवतः अधिकतम 6 प्रतिशत तक हो सकती है. ऐसी स्थिति में, यदि मुद्रास्फीति (जीडीपी डीफ्लेटर द्वारा आंकी गई) 7 प्रतिशत हो, तो सकल घरेलू उत्पाद की न्यूनतम वृद्धि 13 प्रतिशत होगी न कि 13.4 प्रतिशत. दूसरे शब्दों में घटती संख्या सम्मानजनक लगती है क्योंकि डीनोमिनेटर बढ़ा हुआ है. वास्तविक डीनोमिनेटर कम रहने की संभावना है.

इसे देखते हुए वित्त मंत्री 2012-13 और 2013-14 में तथाकथित रेड लाइन्स में उलझे हैं. राजकोषीय घाटा/सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2012-13 में 5.2 प्रतिशत था और 2013-14 में यह 4.8 प्रतिशत होगा. 2016-17 तक यह अनुपात 3 प्रतिशत तक नीचे लाया जाएगा. मोटे तौर पर हर वर्ष आधा प्रतिशत की कमी संभव है. यह मामूली तौर पर अधिक है लेकिन इसे हासिल किया जा सकता है, हालांकि कठिन है, लेकिन शर्त यह है कि 2013-14 में यह 4.8 प्रतिशत पर बनाए रखी जाए. 2012-13 में योजना खर्च में करिश्माई तरीके से कमी करके इसे 5.2 प्रतिशत हासिल किया गया. अधिक दिलचस्प बात यह है कि 2013-14 में इसे 4.8 प्रतिशत कैसे हासिल किया जा सकता है और क्या ये आंकड़े विश्वास योग्य हैं?

कच्चे तेल के मूल्य और विनिमय दरों के बारे में हमेशा अंतर्निहित (अस्पष्ट) अवधारणा रहती है. इसकी अनदेखी की जा सकती है. इसके अलावा समग्र बढ़ोतरी के पक्ष में एक बिंदु यह है कि कर राजस्व (केंद्र का विशुद्ध) में 19.1 प्रतिशत की वृद्धि (2012-13 के संशोधित अनुमान के अनुसार) की संभावना व्यक्त की गई है. वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी के बिना यह संभव नहीं होगी. 2013-14 में 1,72,252 करोड़ रुपये की गैर कर राजस्व प्राप्तियों से संबंधित आंकड़े और भी आशाजनक लगते हैं. यह आशावादी दृष्टिकोण 2012-13 में नदारद था. क्या 2013-14 इससे अलग होगा? क्या योजना और गैर योजना खर्च में कमी लाना संभव होगा अथवा पूरक अनुदान मांगों पर निर्भर रहना होगा. उदाहरण के लिए क्या 2013-14 में सब्सिडी घट कर जीडीपी का 2 प्रतिशत रह जाएगी जो 2012-13 में 2.5 प्रतिशत थी?

(शेष पृष्ठ 95 पर)

गेमिंग-कॅरिअर के रूप में

आज मनोरंजन के क्षेत्र में ऑनलाइन गेमिंग सबसे आकर्षक कार्य है. आप सभी आयु के लोगों को ये खेल- चाहे विडियो गेम हो, हाथ में रखे जाने वाले वायरलैस गेम या पीसी और प्ले स्टेशन एक्स बॉक्स तथा अन्य खेल, खेलते हुए देख सकते हैं. मोबाइल फोन पर गेम खेलना आजकल फैशन हो गया है. बढ़ते हुए ऑनलाइन गेमिंग के प्रचलन से गेम डिज़ाइन और विकास एवं आकर्षक तथा लाभप्रद क्षेत्र बन गया है.

गेमिंग व्यवसाय एक अत्यंत महंगा व्यवसाय है. इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार, डिजाइन, विकास और सुपुर्दगी तक की संपूर्ण प्रक्रिया की लागत 4-10 मिलियन डॉलर तक हो सकती है. इन कार्यों में दो वर्षों तक का समय लगता है. पश्चिमी विश्व में यह एक बहुत विकसित उद्योग है, जबकि भारत में यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में है. अपनी विशेषज्ञता और कम लागत के कारण विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय गेमिंग स्टूडियो अपने कार्य भारतीयों को आउटसोर्स कर रहे हैं.

नासकॉम तथा अन्य लोकप्रिय बाजार अनुसंधान फर्मों के अनुसार भारतीय गेमिंग उद्योग में वर्ष 2013 के अंत तक 53% की वृद्धि और वर्ष 2014 तक लगभग 3100 करोड़ रुपए का व्यवसाय करने की उम्मीद है. ऐसे आकर्षक आंकड़े भारतीयों को ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में एक आकर्षक कॅरिअर के लिए प्रेरित करते हैं. एक अच्छा समाचार यह भी है कि फीफा, स्पाइडरमैन और अन्य जैसी अंतर्राष्ट्रीय विषय वस्तु के अलावा भारतीय विषय वस्तु की भी मांग बढ़ रही है.

भारतीय गेमिंग बाजार में अपनी योग्यता और क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक ऊर्जावान युवाओं के लिए बहुत संभावना है. गेमिंग उद्योग आकर्षक और लाभप्रद है. गेमिंग के क्षेत्र में डेवलपरों, डिजाइनरों, प्रोग्रामरों, कलाकारों और जांचकर्ताओं का कार्य अत्यंत आकर्षक है. प्रोग्रामर कोड बनाने तथा जटिल स्थितियां बनाने के कार्य करते हैं. डिजाइनर गेम की वास्तविकता का अहसास करवाते हैं एवं मनोरंजक बनाते हैं. इनके अलावा एनिमेटर, टैक्सचर और कंसप्ट आर्टिस्टों, ऑडियो कम्पोजरों तथा निर्माता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. जैसे टेस्टर ऑनलाइन गेम के अलग-अलग चरणों के कार्य और किसी बग के होने पर उसकी जानकारी देना जैसा चुनौतिपूर्ण कार्य करते हैं. इस प्रकार यह उद्योग पूरी दुनिया में गेम प्रेमियों के मनोरंजन करने और अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है.

ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में एक सफल कॅरिअर बनाना उतना आसान नहीं है. उम्मीदवार में अत्यधिक सहिष्णुता, स्वप्रेरणा, उत्साह, सृजनात्मकता अभिवृत्ति जैसे गुण होने चाहिएं. तकनीकी रूप से दक्ष होना और कलाकार जैसे भी गुण होने चाहिएं.

अकादमिक रूप से, व्यक्ति के पास कम्प्यूटर विज्ञान अथवा ललित कला में डिग्री अथवा डिप्लोमा होना चाहिए. उम्मीदवार कोई भी अल्पकालिक पाठ्यक्रम अथवा डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर गेम डेवलपमेंट पाठ्यक्रम चुन सकते हैं. अपनी रुचि के अनुसार पात्रों के निर्माण, 3डी एनिमेशन और ग्राफिक्स, यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग तथा ऑडियो प्रोग्रामिंग जैसे अन्य पाठ्यक्रमों का भी चुनाव कर सकते हैं. एक प्रोग्रामर बनने के लिए उम्मीदवार के पास फ्लैश, एएसपी, वैप, जावा, सी++ और शॉकवेव की पूरी जानकारी होनी चाहिए. एक प्रशिक्षु आर्टिस्ट के पास माया 3डीएस मैक्स, अडोब फोटोशॉप, डीपपेंट, जाब्रश तथा अन्य डिजिटल, स्वस्पटिंग एप्लीकेशन और अन्य चित्रकारी की जानकारी होनी चाहिए. इस क्षेत्र में कार्य करने के अनेक अवसर हैं. किसी भी व्यक्ति को गेम टेस्टिंग के विशेष क्षेत्रों के अलावा थ्रीडी गेम, वेब थ्रीडी ग्राफिक्स, साइमलटर ग्राफिक्स और इंटरएक्टिवडेमो के क्षेत्र में जैपेक, हंगामा, विप्रो ई 4ई और ऐसी अनेक कम्पनियों में प्लेसमेंट मिल सकता है. आपके पद के अनुसार वेतन 12,000-20,000 रुपए के बीच में होता है.

कालेज एवं पाठ्यक्रम

कॉलेज	पाठयक्रम	पात्रता	प्रवेश	वेबसाइट
आईसीएटी डिजाइन एवं मीडिया कॉलेज, हैदराबाद	बी.ए. डिजिटल मीडिया -गेम डिजाइन एवं गेम डेवलपमेंट में विशेषज्ञता	+2	अभिरुचि परीक्षा	www.icat.ac.in
	बी.एस.सी. डिजिटल मीडिया गेम डिजाइन एवं गेम डेवलपमेंट में विशेषज्ञता			
	गेम डिजाइन एवं गेम विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा			
एम.ए.ई.ई. आर का एम.आई.टी. डिजाइन संस्थान, पुणे एबेंट यूनिवर्सिटी, डुंडी स्कॉटलैंड	बी.ए.(ऑनर्स) कम्प्यूटर आर्ट्स फॉर गेमिंग	+2	प्रवेश परीक्षा	www.mitid.edu.in
	कम्प्यूटर आर्ट्स फॉर गेमिंग में स्नातकोत्तर कार्यक्रम	स्नातक		
एरीना एनीमेशन, हैदराबाद	एरीना गेम कला एवं डिजाइन पाठ्यक्रम	+2	-	www.arena-multimedia.com
एनीमेशन एवं गेमिंग अकादमी, गुड़गांव	बी.एससी गेमिंग	+2	-	www.aaggurgaon.in
	एम.एससी गेमिंग	स्नातक	-	
मीडिया कला एवं विज्ञान कॉलेज चेन्नै	बी.एससी. गेमिंग	+2	-	http://masc.asia
एम्प्लीफाइ माइंडवेयर, पुणे	एनीमेशन एवं गेमिंग में विज्ञान स्नातक	+2 (एम.पी.सी) तथा 50 प्रतिशत अंक	प्रवेश परीक्षा सामूहिक विचार-विमर्श तथा निजी साक्षात्कार में प्रदर्शन	www.amplify.mind.com
अंतर्राष्ट्रीय कम्प्यूटर ग्राफिस अकादमी हैदराबादए जे. एन.टी.यू. के सहयोग से	मल्टीमीडिया स्नातक	+2 एवं न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक	-	www.iacg.inf
	मल्टीमीडिया में एम.एस.सी.	स्नातक तथा न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक		
जवाहरलाल नेहरू वास्तु कला एवं ललित कला विश्वविद्यालय, हैदराबाद	एक विशेषज्ञता के रूप में एनीमेशन सहित बी.एफ.ए.	+2	प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन	http://jnafau.ac.in
बीआईटीएस जयपुर	बी.एससी. एनीमेशन एवं मल्टीमीडिया	10+2 एवं न्यूनतम एवं प्रदर्शन 60 प्रतिशत अंक तथा 10+2 स्तर पर सभी अपेक्षित विषयों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक	सृजन अभिरुचि परीक्षा में मैरिट, रैंक एवं प्रर्दशन	www.bitmesha.in
अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नै	मल्टीमीडिया में एम.टेक	सी.एस.ई./आई.टी/ई.ई.ई. ई.सी.ई. या इलेक्ट्रानिकी में बी.ई./बी.टेक	प्रवेश परीक्षा/गेट में में प्रर्दशन	www.annauniv.edn.
एस.आर.एम. विश्वविद्यालय, कांचीपुरम जिला	मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी में एम.टेक	किसी भी शाखा में बी.ई./बी.टेक या कम्प्यूटर विज्ञान/आई.टी. में एम.एससी. या एम.सी.ए.	एम. आर. एम. विश्वविद्यालय की अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा (एस.आर.एम. ई.ई.ई.) या गेट में प्रदर्शन	www.srmuniv.ac.in

(यह लेख सिकंदराबाद (आंध्र प्रदेश) स्थित TMIE2E अकादमी कॅरिअर केन्द्र से प्राप्त हुआ है. ई-मेल : faqs@tmie2e.com)

साप्ताहिक हलचल

(02.03.2013 से 08.03.2013)

- *केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पासपोर्ट, पेंशन, जन्म, मृत्यु और जाति प्रमाणपत्र जैसी सेवाओं को समयबद्ध तरीके से नागरिकों तक पहुंचाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है.*
- *एक अप्रैल से मनरेगा कामगारों को अधिक पारिश्रमिक मिलेगा.*
- *मल्टी-बैरल रॉकेट लांचर (एमबीआरएल) के जरिए देश में निर्मित ''पिनाका'' रॉकेटों का ओडिशा के चांदीपुर में सफल परीक्षण किया गया.*
- *वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए उत्तराखंड वन और पुलिस विभाग को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है. इससे यह राज्य विश्व के दस पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में शामिल हो गया है. सीआईटीईएस (कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेन्जर्ड स्पीशेस ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा) के 16वें कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान बैंकॉक में यह पुरस्कार प्रदान किया गया.*
- *वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज की सहायक एजेंसी मूडीज एनेलिटिक्स ने 2013 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के पूर्वानुमान में संशोधन कर इसे 5.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया है. इसके अलावा 2014 के बाद से 8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की संभावना भी व्यक्त की गई है.*
- *बांग्लादेश ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ढाका में देश के सर्वोच्च 'मुक्ति संग्राम सम्मान' से सम्मानित किया.*
- *स्वर्गीय सितार वादक रवि शंकर को सांस्कृतिक सौहार्द के लिए वर्ष 2012 का प्रथम टैगोर पुरस्कार प्रदान किया गया है. इस पुरस्कार के तहत एक करोड़ रुपए की राशि, शॉल, शलाका और प्रशस्ति पत्र शामिल है.*
- *दिल्ली में 16 दिसंबर को सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई पीड़िता को अमेरिकी सरकार मरणोपरांत वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित करेगी. यह पुरस्कार अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा दिया जाएगा.*
- *दुबई टेनिस चैंपियनशिप में महेश भूपति ने अपने फ्रांसीसी जोड़ीदार माइकल लोड्रा के साथ मिलकर रॉबर्ट लिंडस्टेट और नेनाद जिमोनजिक की जोड़ी को हराकर 2013 की अपनी पहली खिताबी जीत दर्ज की.*
- *हैदराबाद में दूसरे क्रिकेट टैस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी.*
- *ओलंपिक चैंपियन जेन सुर ने महिला पोल वॉल्ट में अमेरिकी इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप के तहत 5.02 मीटर का नया कीर्तिमान स्थापित किया.*

फार्म IV

(नियम देखें)

1. प्रकाशन का स्थान :	दिल्ली
2. आवर्तन :	साप्ताहिक
3. मुद्रक का नाम :	दि अमर उजाला प्रकाशन लिमिटेड
क्या भारत के नागरिक हैं? :	हां
(यदि विदेशी हैं, तो मूल देश के नाम का उल्लेख करें)	
पताः	दि अमर उजाला प्रकाशन लिमिटेड, सी 21 एवं 22, सेक्टर-59, नोएडा-201301
4. प्रकाशक का नाम :	सुश्री ईरा जोशी
क्या भारत की नागरिक हैं :	हां
पता :	अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पूर्वी खण्ड-IV, लेवल-V, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
5. संपादक का नाम :	डॉ. ममता रानी
क्या भारत की नागरिक हैं? :	हां
(यदि विदेशी हैं तो मूल देश का नाम बताएं)	
पता :	संपादक, रोज़गार समाचार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पूर्वी खंड-IV, लेवल-V, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
6. उन व्यक्तियों के नाम और पते, जो समाचार पत्र के स्वामी अथवा साझेदार अथवा कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक शेयरधारक हैं :	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन

मैं, ईरा जोशी, एतद्द्वारा घोषणा करती हूं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी अच्छी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है.

sd/

(ईरा जोशी)

प्रकाशक

सं. ए. 12015/1/2012/-प्रशासन-I

कृषि मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी तथा मछली पालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली

पशुपालन, डेयरी तथा मछली पालन विभाग ने निम्न पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है:

क्र. सं.	पदनाम, वर्ग तथा वेतनमान	रिक्तियों की सं.	नियुक्ति का तरीका	पूर्व संदर्भ सं. तथा तिथि
1.	संयुक्त आयुक्त (पशुपालन)	02	प्रतिनियुक्ति (अल्प-कालीन अनुबंध आधारित सहित)	फाइल सं. ए-12025/3/2012-प्रशासन-I तिथि 16.11.2012 तथा 05.12.2012 तथा रोज़गार समाचार के विज्ञापन की तिथि 17 से 23 नवंबर, 2012 तथा 22 से 28 दिसंबर, 2012
2.	उप-आयुक्त (मछली पालन) सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'अ' पीबी-3 रु. 15600-39100 + 5400/- (ग्रे.वे.)	01	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध आधारित पद सहित) (संयुक्त प्रविधि)	फाइल सं. ए-12023/4/2011-प्रशासन-I तिथि 16.11.2012 तथा रोज़गार समाचार के विज्ञापन की तिथि 17 से 23 नवंबर, 2012
3.	उप-निदेशक (एक्वेटिक क्वारेंटाइन) सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'अ' पीबी-3, रु. 15600-39100+ 6600/- (ग्रे.वे.)	01	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध आधारित पद सहित) (संयुक्त प्रविधि)	फाइल सं. ए-12023/4/2011-प्रशासन-I तिथि 16.11.2012 तथा रोज़गार समाचार के विज्ञापन की तिथि 17 से 23 नवंबर, 2012
4.	उप-आयुक्त (फिशिंग हार्बर) सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'अ' पीबी-3, रु. 15600-39100 + 7600/- (ग्रे.वे.)	01	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध आधारित पद सहित) (संयुक्त प्रविधि)	फाइल सं. ए-12023/5/2011-प्रशासन-I तिथि 16.11.2012 तथा रोज़गार समाचार के विज्ञापन की तिथि 17 से 23 नवंबर, 2012
5.	सहायक आयुक्त (मछली पालन) सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'अ' पीबी-3, रु. 15600-39100+ 6600/- (ग्रे.वे.)	04	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध आधारित पद सहित)	फाइल सं. ए-12023/2/2011-प्रशासनिक-I तिथि 16.11.2012 तथा तिथि 17 से 23 नवंबर, 2012 के रोज़गार समाचार का विज्ञापन
6.	सहायक निदेशक (एक्वेटिक क्वारंटाइन) सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'अ' पीबी-3, रु. 15600-39100 + 5400/- (ग्रे.वे.)	01	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध आधारित पद सहित) (संयुक्त प्रविधि)	फाइल सं. ए-12023/6/2011-प्रशासनिक-I तिथि 16.11.2012 तथा तिथि 17 से 23 नवंबर, 2012 के रोज़गार समाचार का विज्ञापन
6.	सहायक आयुक्त (फिशिंग हार्बर) सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'अ' पीबी-3, रु. 15600-39100 + 6600/- (ग्रे.वे.)	01	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध आधारित पद सहित) (संयुक्त प्रविधि)	फाइल सं. ए-12023/4/2008-प्रशासनिक-I तिथि 16.11.2012 तथा तिथि 17 से 23 नवंबर, 2012 के रोज़गार समाचार का विज्ञापन

2. पात्रता मापदंड जैसे शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जीवन परिचय (बायोडाटा) इत्यादि के लिए आवेदक हमारे विभाग की वेबसाइट : http://dahd.nic.in पर जाएं. सभी प्रकार से पूर्ण किया गया आवेदन पद विशेष के लिए आवेदक इस पते पर भेजें : श्री डी. बनर्जी, अवर सचिव (प्रशासन) कमरा नं. 436-ए, कृषि भवन, नई दिल्ली. आवेदन उपरोक्त पते पर इस विज्ञापन के प्रकाशन के **60 दिनों के भीतर** पहुंच जाना चाहिए.

3. जिस पद के लिए आवेदन किया गया है, उसका नाम साफ बड़े अक्षरों में उस लिफाफे के ऊपर लिखें, जिसमें आवेदन पत्र रखा गया हो.

4. जिन व्यक्तियों ने पहले आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है.

अवर सचिव (प्रशासन)

(डी बनर्जी) अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, एएचडी एवं मछली पालन विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली

रो.स. 50/17

एन एस आई सी NSIC ISO 9001 : 2008

एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र

(भारत सरकार का उद्यम)

बी-24, एक्काडुथंगल, चेन्नै-600032

फोन: 044-22252335/6/7, फैक्स : 044-22254500

ई-मेल : chentrg@nsic.co.in

प्रवेश-सूचना-बैच 15.4.2013 से प्रारंभ हो रहा है.

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिक रोज़गार योग्य

क्र. सं.	पाठ्यक्रम विवरण	अवधि	शुल्क	पात्रता
1.	पीएलसी, स्काडा-कैलीब्रेशन तकनीकों सहित	6 सप्ताह	7000/-	बीई,ईईई, ईसीई, ई.एवं आई. में डिप्लोमा
2.	आरटीओ.एस का प्रयोग करते हुए एम्बैडेड डिजाइन	3 महीने	12000/-	ई.ई.ई./ई.सी.ई./सी.एस./ई.एवं आई./आई.टी. में बी.ई/डिप्लोमा.
3.	सिस्को रूट का प्रयोग करते हुए उच्च नेटवर्किंग	2 महीने	10000	कोई भी डिग्री
4.	कैड सॉफ्टवेयर-केटिया या सॉलिड वर्क्स का प्रयोग करते हुए 3डी डिज़ाइन	4 सप्ताह	6000/-	यांत्रिक इंजी./ड्राफ्ट्समेन (यांत्रिक) में डिग्री/डिप्लोमा
5.	3डी स्कैनिंग एवं सीएमएम तकनीकों (रिवर्स इंजीनियरी तकनीकों) का प्रयोग करते हुए उत्पाद डिजाइन की प्रस्तुति	1 सप्ताह	200/-	
6.	सॉलिड वर्क्स/या यूनिग्राफिक्स या कैटिया या इनवेंटर या प्रो.ई. का प्रयोग करते हुए 3डी डिजाइन एवं मॉडलिंग	4 सप्ताह	6000/-	
7.	यूनिग्राफिक्स का प्रयोग करते हुए कैड एवं कैम	4 सप्ताह	9000/-	
8.	सी.एन.सी. प्रोग्रामिंग एवं परिचालन (मिलिंग एवं टार्निंग)	6 सप्ताह	7000/-	यांत्रिक, एयरोनॉटिक्स ऑटोमोबाइल में बी.ई./डिप्लोमा तथा आई.टी.आई.
9.	ऊर्जा प्रबंधन एवं कैलीब्रेशन तकनीक	4 सप्ताह	7000/-	ई.ई.ई.,ई.सी.ई.,ई. एवंआई., यांत्रिक इंजी. में बी.ई./डिप्लोमा
10.	प्रेशर, थर्मल एवं इलेक्ट्रो तकनीकी पैरामीटर्स पर कैलीब्रेशन	2 सप्ताह	4000/-	इंजी. में डिग्री/डिप्लोमा/आई.टी.आई.
11.	मशीनिस्ट/टर्नर/फिटर/ इलेक्ट्रीशियन (गैर-आई.टी.आई.)	प्रत्येक एक वर्ष	प्रत्येक 5000/-	दसवीं कक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण

आयु: 18 से 35 वर्ष अ.जा./अजजा/शावि/भूतपूर्व सैनिकों के लिए नियमानुसार छूट. यथा लागू सर्विस टैक्स अतिरिक्त है. सादे कागज पर पाठ्यक्रम का नाम, ई-मेल आई.डी/फोन नं. के विवरण, प्रमाणपत्रों की प्रतियों और **''एन.एस.आई.सी लिमिटेड एकाउंट एन.टी.एस.सी., चेन्नै''** के पक्ष में देय रु. 250/- के डिमांड ड्राफ्ट के साथ जीवन-वृत्त (अजा/अजजा के उम्मीदवार शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं) **29.3.2013** तक उक्त पते पर भेज दें. होस्टल सुविधा केवल पुरुषों के लिए उपलब्ध है. उम्मीदवारों को सूचना ई-मेल/फोन/डाक द्वारा भेजी जाएगी.

महाप्रबंधक

रो. स. 50/27

रक्षा खरीद...

(पृष्ठ 1 का शेष)

साथ ही इससे व्यापक नागरिक औद्योगिक आधार भी खड़ा होगा.

एक सैनिक के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण और हतोत्साहित करने वाली बात है कि उसके पास नवीनतम हथियारों से लैस उपद्रवी या उग्रवादियों से निपटने के लिए एक विश्वसनीय राइफल तक भी नहीं होती है. अतः आरंभिक चरण में एक लंबी चौड़ी ख़रीद प्रक्रिया को लांघते हुए यह अनिवार्यता है कि त्वरित आयातों के जरिए बुनियादी ज़रूरतों को तत्काल पूरा किया जाए. लागत बचाने के लिए एक राइफल का चुनाव रक्षा सेनाओं के साथ-साथ अर्द्ध सैन्य बलों की ज़रूरतें पूरा करने के वास्ते किया जाए. साथ ही साथ भारत में निर्धारित निजी क्षेत्र इकाइयों को प्रौद्योगिकी का अंतरण किया जाना चाहिए.

दूसरी तरफ बोझिल लालफीताशाही और अनिर्णायक स्थिति को हटाना बेहद ज़रूरी है. भारतीय वायु सेना द्वारा उड़ान के दौरान ईंधन भरने के वास्ते छह विमानों के चयन के संबंध में आमंत्रित की गई निविदा को रक्षा मंत्रालय की लिपिकीय मानसिकता के कारण ही रद्द कर दिया गया था. व्यंगात्मक स्थिति ये है कि पुनः आमंत्रित की गई निविदा में उसी कंपनी की ही वरीयतन बोलीदाता के तौर पर पहचान की गई है. इससे रक्षा मंत्रालय की ओर से होने वाली अत्यधिक देरी के प्रति उसकी अवांछित मानसिकता साफ़ झलकती है. मौजूद ख़तरों को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायु सेना के लिए अपेक्षित हार्डवेयर की समय पर उपलब्धता प्रक्रियात्मक औपचारिकाताओं से कहीं ऊपर है. इसी प्रकार अपनी खुद की कमियों को दूर किये बग़ैर यदि कंपनियों को काली सूची में डाला जाता रहा तो इससे केवल मुसीबत ही पैदा होगी. उदाहरण के लिए यदि 155 एमएम आर्टिलरी गन बनाने वाली विश्व में केवल पांच ही कंपनियां हैं और उनमें से तीन काली सूची में हैं तो इससे प्रतिस्पर्द्धा समाप्त हो जाएगी और देश अपने धन का सही मूल्य प्राप्त करने से वंचित हो जाएगा. भारत के लिए व्यवसाय के नियम निष्पक्ष और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप होने चाहिए, ताकि इससे उसके स्वयं के आधुनिक रक्षा औद्योगिक परिसर खड़े करने में सफलता हासिल हो सके. रक्षा प्रौद्योगिकियों की तीव्र गति के साथ आज हथियारों के संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना संभव नहीं है.

अतः भारत को भी प्रमुख और अन्य प्रकार के उपकरणों की किस्मों के अनुसंधान एवं विकास का एक महत्वपूर्ण हब बनकर रक्षा उपकरणों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक हिस्सा बनना चाहिए. भारत की मानसिक सुस्ती से पार पाए बग़ैर युद्धक प्रौद्योगिकी तेज़ी के साथ समुद्र, ज़मीन और हवा में पायलट हीन सुदूर नियंत्रित वाहनों और हथियार प्रणाली की तरफ अग्रसर हो रही है. असल में अब नई दिल्ली में बैठा कोई भी व्यक्ति दुश्मन के घर के अंदर तक झांक सकता है और सुदूर नियंत्रित पायलट हीन ड्रोन की मदद से मिसाइल दाग़ कर उभरते ख़तरे से निपटा जा सकता है. हम नए भू-राजनैतिक वातावरण में मौजूद अनुकूल अवसरों के बावजूद ऐसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के आसपास भी नहीं है. पूर्व में प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष के विकसित होने में एक दशक लगता था. अब युद्धक प्रौद्योगिकी एक वर्ष के भीतर ही पुरानी पड़ जाती है. इसकी अपार संभावनाएं हैं कि युद्धक क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय उन्नयनों की तीव्र गति के इस युग में जब तक 126 एमएमआरसीए सौदे को अंतिम रूप दिया जाता है तब तक हो सकता है कि ओईएम द्वारा प्रस्तुत की गई प्रौद्योगिकी बहुत अधिक पुरानी न हो जाए.

भारतीय सशस्त्र बलों को देश पर मंडराते ख़तरों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप में तब तक तैयार नहीं किया जा सकता जब तक कि रक्षा मंत्रालय पारदर्शिता, परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन, धन का संहार करने वाले रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्तर को 49 प्रतिशत तक बढ़ाते हुए पश्चिमी रक्षा उद्योगों के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने और रक्षा ख़रीद प्रक्रिया को लिपिकीय प्रक्रियाओं की बजाए राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति से जोडने के लिए कदम नहीं उठाएगा.

(लेखक: इंडियन डिफेंस रिव्यू के संपादक हैं. ई मेल: bharat.verma@indiandefencereview.com

(उपर्युक्त लेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं और ये ज़रूरी नहीं कि यह रोज़गार समाचार की राय हो)

अर्थव्यवस्था और...

(पृष्ठ 1 का शेष)

अलग तरीके से व्यक्त करते हुए बजट में योजना व्यय में प्रभावशाली बढ़ोतरी 2012-13 के संशोधित अनुमान पर आधारित है न कि बजट अनुमान पर. किंतु, 2012-13 से भिन्न राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है. बजट में 5,42,499 करोड़ रुपये के ऋण संबंधी आंकड़े दिए गए हैं. 2012-13 में संशोधित अनुमान के अनुसार खर्च में कटौती के बावजूद देनदारी 5,20,925 करोड़ रुपये थी. क्या इसका यह अर्थ है कि सरकार खर्च न की गई उस नकद राशि पर निर्भर है जिसे 2013-14 में ले जाया जा रहा है? अतः जहां एक तरफ फिजूल खर्ची पर नियंत्रण के उपायों के लिए बजट की तारीफ की जानी चाहिए वहीं दूसरी तरफ आंकड़ों पर भरोसा करते समय उचित सावधानी बरती जानी चाहिए.

बजट में कहा गया है कि ''सभी फ्लैगशिप यानी प्रमुख कार्यक्रमों को पूरी तरह और समुचित रूप में वित्त पोषित किया जाएगा''. फ्लैगशिप से यह छवि उभरती है कि जैसे कोई एडमिरल बेड़े पर नियंत्रण रखता है. और हां, हमारे पास संदिग्ध प्रभावोत्पादकता वाले केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों का एक बेड़ा है. बजट भाषण में कहा गया है कि ''सरकार केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता कार्यक्रमों के प्रसार के प्रति चिंतित है. 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में इन कार्यक्रमों की संख्या 173 थी. मैं प्रसन्नतापूर्वक यह घोषणा करता हूं कि इन कार्यक्रमों को 70 तक सीमित किया जाएगा''. बी के चतुर्वेदी समिति ने सिफारिश की थी कि इन कार्यक्रमों को कम करके 59 तक सीमित किया जाए और 17 फ्लैगशिप कार्यक्रमों में उनका पुनर्गठन किया जाए. यदि बजट खर्च संबंधी प्रावधान केवल इन्हीं कार्यक्रमों तक सीमित होते तो बात समझी जा सकती थी, हालांकि सभी सामाजिक क्षेत्र राज्य और स्थानीय निकायों का विषय हैं. यहां कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं. बजट के पैरा 71 में कहा गया है कि ''नौकरियों, उत्पादन और निर्यात में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की बहुत भारी भूमिका है. इनमें से कई उद्यम छोटे और मध्यम हैसियत से जुड़े लाभों को खोने के डर से और तरक्की नहीं कर पाते हैं. उन्हें बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मेरा प्रस्ताव है कि जिस श्रेणी में उन्हें यह लाभ मिलता है, उस श्रेणी से आगे बढ़ने के बावजूद उन्हें अगले तीन वर्ष तक यह लाभ मिलता रहे''. वे लाभों की वजह से विकास नहीं करते और फिर कोई कहे कि उन्हें और लाभ दिए जाएं. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में महिला बैंक की क्या आवश्यकता है? बजट के पैरा 90 में कहा गया है, ''10,000 या इससे अधिक की आबादी वाले प्रत्येक भारतीय कस्बे में भारतीय जीवन बीमा निगम का एक कार्यालय होगा तथा सार्वजनिक क्षेत्रीय साधारण बीमा कंपनी का कम से कम एक कार्यालय होगा. मेरा इस लक्ष्य को 31.3.2014 तक हासिल करने का प्रस्ताव है''. यह वित्त मंत्री का लक्ष्य कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से इसे हासिल करना एलआईसी और सामान्य बीमा कंपनियों का काम है. क्या किसी को एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेश और एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बीच अंतर करने का प्रयास करना चाहिए? निश्चित रूप से महिला, युवा और निर्धन महत्वपूर्ण हैं. महिलाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण है. लेकिन क्या निर्भया कोष इसका उत्तर है? इन सभी के बीच खर्च को युक्तिसंगत बनाने का वास्तविक प्रयास दिखाई नहीं देता. कर की दिशा में भी समान स्थिति दिखाई देती है. पैरा 145 इसका एक उदाहरण है. ''अचल संपत्तियों में किए जाने वाले संव्यवहारों का सामान्यतया कम मूल्यांकन और कम रिपोर्टिंग की जाती है. आधे संव्यवहारों में संबंधित पक्षकारों की पेन संख्या नहीं दी जाती है. ऐसे संव्यवहारों की रिपोर्टिंग और पूंजी अभिलाभों को सुधारने की दृष्टि से, अचल संपत्ति, जहां प्रतिफल मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक है, के अंतरण के मूल्य पर 1 प्रतिशत की दर पर टीडीएस लागू करने का प्रस्ताव करता हूं. कर वंचना से अलग, उच्च स्टाम्प मूल्य और अनुपालन संबंधी लागत को इसका कारण बनाया गया है. टीडीएस लागू करने से कम मूल्य रिपोर्ट किए जाने की प्रवृत्ति को और भी बढ़ावा मिलेगा. इसी प्रकार पैरा 181 देखिए ''इस समय, शराब न परोसने वाले वातानुकूलित रेस्तराओं पर सेवा कर लागू नहीं है. यह अंतर बनावटी है तथा मैं, सभी वातानुकूलित रेस्तराओं पर सेवा कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं''. क्या वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित रेस्तराओं के बीच यह अंतर कृत्रिम नहीं है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसी रेस्तरां में वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित खंड हैं? सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क दोनों के बारे में ऐसे कई विचारणीय पहलू हैं. यदि आप स्वच्छता चाहते हैं तो विवेकाधिकार कम किए जाने चाहिए और मानकीकरण अपनाया जाना चाहिए.

निकट भविष्य में जीएसटी से शुरुआत करें तो सेवा कर 12 प्रतिशत मानकीकृत होना चाहिए. यहां भी चिंतन और युक्तिसंगतता का अभाव दिखाई देता है.

2013-14 का बजट जहां एक तरफ खर्च बढ़ने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने पर बल देता है, वहीं दूसरी तरफ उसे घाटे संबंधी आंकड़ों, व्यय और कर प्रस्तावों के प्रति संशयवादी होना चाहिए.

(लेखक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, दिल्ली में प्रोफ़ेसर हैं. ई-मेल - bdebroy@gmail.com)

दिल्ली पोस्टल पंजीकरण संख्या डीएल-एसडब्ल्यू 1/4100/2012-14 यू. (सी.)-107/2012-14 पूर्व शुल्क के बिना डाक में डालने की अनुमति आर.एन.आई.28729/76 एन.डी.पी.एस.ओ. नई दिल्ली 16/18.03.2013 (₹ 8) प्रकाशन तिथि : 14.03.2013

श्रीनगर, लेह, कालिम्पोंग, इम्फाल, दीमापुर, अगरतला, दुलियाजॉन, करीमगंज, छाबुआ, दीफू, डिब्रूगढ़, तेजपुर, हेल्लाकांडी, मरियानी, जोरहाट, शिलांग, डिगबोई, सिल्चर तथा पोर्टब्लेयर के लिए विमान सेवा 20 पैसे अतिरिक्त

हुनर से रोज़गार

एनएचएफडीसी: विकलांगों को सशक्त करने के प्रति अग्रसर

हर्ष भाल

राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) का सपना देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए स्व रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना, हुनर को निखारने में मदद करना तथा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है.

भारत सरकार के विकलांग मामलों के विभाग के तहत राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) विकलांग व्यक्तियों को अपना काम-धंधा शुरू करने के साथ पेशेवर/तकनीकी शिक्षा के लिए भी रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करा रहा है. एनएचएफडीसीए राज्यों में अपनी एजेंसियों (स्टेट चैनलाइज़िंग एजेंसीज़) या प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए कौशल प्रशिक्षण के लिए 100 फीसदी अनुदान भी प्रदान करता है. प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान हर प्रशिक्षु को प्रति माह 1000/- रुपए का स्टाइपेंड दिया जाता है. निगम की ऋण संबंधी योजनाओं के तहत 25.00 लाख रूपए तक के कर्ज़ के लिए विकलांग महिलाओं के लिए ब्याज दर सबसे कम 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष है और उच्चतम दर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष है. तकनीकी और पेशेवर शिक्षा के लिए एनएचएफडीसी दो छात्रवृत्ति योजनाएं भी चला रहा है. उच्च शिक्षा के लिए विकलांग विद्यार्थियों को हर साल 1500 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं. छात्रवृत्ति की राशि औसतन 50,000/- रुपए है जो पाठ्यक्रम शुल्क, छात्रावास शुल्क, अध्ययन सामग्री और उनके इस्तेमाल में आने वाले एक बार के सहायक उपकरणों पर निर्भर करती है. देश में लगभग 2 करोड़ 19 लाख विकलांग व्यक्ति हैं तथा एनएचएफडीसी की सेवाएं उन्हें अपना काम-धंधा शुरू करने, हुनर को और निखारने तथा भारत और विदेश में उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बढ़ावा देने में इस्तेमाल की जा सकती हैं.

एनएचएफडीसी का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को लाभकारी कार्यों में लगाकर दूसरों पर उनकी निर्भरता कम करने के साथ खराब आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से दूर करके उन्हें सशक्त बनाना है ताकि वे पूरे आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा के साथ सामाजिक और आर्थिक स्तर पर अपनी पहचान बना सकें. विकलांग व्यक्तियों के फायदे के लिए इस शीर्ष निगम की मुख्य गतिविधियां इस प्रकार हैं:

एनएचएफडीसी राज्यों में अपनी एजेंसियों (स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज़) के जरिए देशभर में विकलांग व्यक्तियों के लिए रियायती दर पर ऋण की सुविधा का विस्तार कर रहा है. पात्रता मानदंड, योजनाओं और अन्य जानकारी एनएचएफडीसी की वेबसाइट (www.nhfdc.in) पर उपलब्ध है. चालू वर्ष में देश में लगभग 10,900 विकलांग व्यक्तियों को अपना काम-धंधा शुरू करने हेतु रियायती दर पर ऋण देने के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि वितरित करने का लक्ष्य है. जिन गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसमें विकलांग व्यक्तियों की सुविधा/पसंद के अनुसार एसटीडी/पीसीओ बूथ, मोबाइल की मरम्मत, सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर, किराने की दुकान, पान की दुकान, जनरल स्टोर, व्यावसायिक वाहन खरीदना आदि शामिल है. वास्तव में ऐसे किसी भी गतिविधि के लिए कर्ज़ दिया जा सकता है जिससे लाभार्थी को कुछ आमदनी हो.

हर विकलांग व्यक्ति रियायती दर पर ऋण पाने का लाभ उठा सकता है (4 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की ब्याज दर)

विकलांग व्यक्ति को जिले में किसी प्रतिनिधि के साथ हमारी एजेंसी में संपर्क करना चाहिए. पात्रता के लिए शर्तें इस प्रकार हैं:

(1) विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए.

(2) आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

आपके राज्य में स्थित एजेंसी के बारे में जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (www.nhfdc.nic.in) देखें.

एनएचएफडीसी विकलांग व्यक्तियों को निम्नलिखित दरों पर 25 लाख रूपए तक के स्व रोज़गार उद्यम के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराता है.

प्रति वर्ष ब्याज दर

परियोजना लागत	महिला	पुरुष
50,000/- रुपए तक	4 प्रतिशत	5 प्रतिशत
50,000/- रुपए से अधिक और 5.00 लाख रुपए तक	5 प्रतिशत	6 प्रतिशत
5.00 लाख रुपए से अधिक	7 प्रतिशत	8 प्रतिशत
भारत में शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक और विदेश में शिक्षा के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण	3.5 प्रतिशत	4 प्रतिशत

एनएचएफडीसी राज्य में अपनी एजेंसियों (स्टेट चैनलाइज़िंग एजेंसीज़) के ज़रिए विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा रहा है जहां प्रशिक्षण का पूरा खर्च निगम उठाता है. इसके अलावा एनएचएफडीसी प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान हर प्रशिक्षु को सहायता के रूप में प्रति माह 1,000/- रुपए का स्टाइपेंड भी देता है. चालू वर्ष के दौरान देश के 1340 विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है. वर्तमान में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के तहत चल रहे व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों (वीआरसी) के जरिए विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान है. देश में 20 व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों की प्रशिक्षण ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं.

एनएचएफडीसी देश में उच्च/तकनीकी/पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए दो छात्रवृत्ति योजनाएं चला रहा है. इन योजनाओं के तहत 1500 विद्यार्थियों को हर साल छात्रवृत्तियां दी जाती हैं. छात्रवृत्ति राशि में पाठ्यक्रम शुल्क, छात्रावास/रख-रखाव शुल्क, पुस्तकें और स्टेशनरी खर्च तथा विकलांग व्यक्तियों के इस्तेमाल में आने वाले एक बार के सहायक उपकरण शामिल हैं. हर विद्यार्थी के लिए प्रतिवर्ष राशि औसतन 50,000/- रुपए है.

इन छात्रवृत्तियों की विस्तृत जानकारी एनएचएफडीसी की वेबसाइट (www.nhfdc.nic.in) पर उपलब्ध है.

छात्रवृत्ति योजनाएं

न्यास कोष (ट्रस्ट फंड)

* हर वर्ष पात्र विकलांग विद्यार्थियों को भारत के मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 50,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से 1000 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं.

* 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए आरक्षित हैं.

आवेदक को इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए शैक्षिक वर्ष में किसी भी समय ऑनलाइन (www.nhfdc.nic.in) आवेदन करना होगा.

* पूर्ववर्ती तिमाही में प्राप्त आवेदनों के लिए छात्रवृत्तियां तिमाही आधार पर दी जाएंगी.

राष्ट्रीय कोष

* हर वर्ष पात्र विकलांग विद्यार्थियों को उच्च शैक्षिक/पेशेवर या तकनीकी योग्यता के लिए 12,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से 500 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं.

* 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए आरक्षित हैं.

* आवेदक को छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन (www.nhfdc.nic.in) आवेदन करना होगा और इस योजना के तहत एक शैक्षिक वर्ष में एक बार छात्रवृत्ति दी जाएगी.

एनएचएफडीसी सभी प्रकार की उच्च शिक्षा, पेशेवर और तकनीकी शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 3.5 प्रतिशत की दर पर (महिला विद्यार्थियों हेतु) और पुरुष विद्यार्थियों के लिए प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की दर से शिक्षा ऋण भी उपलब्ध करा रहा है. यह दरें बाज़ार की दरों की तुलना में बहुत कम हैं. भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना के तहत जहां कहीं स्वीकार्य हो विद्यार्थियों के लिए इन दरों में और रियायत दी गई है.

इसके अतिरिक्त सरकार ने 5000 करोड़ रुपए की राशि के साथ ऋण गारंटी कोष का प्रस्ताव किया है. इस कोष के अंतर्गत बिना कुछ गिरवी रखे या बगैर किसी तीसरे पक्ष की गारंटी के 7.5 लाख रूपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान करना शामिल होगा.

एनएचएफडीसी ने हाल ही में विकलांग विद्यार्थियों के इस्तेमाल में आने वाले सहायक उपकरणों के लिए रियायती ऋण भी शामिल किया है. इससे सरकारी के साथ-साथ निजी क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों की क्षमता बढ़ेगी और बड़े स्तर पर उनके लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे. युवा विकलांग पेशेवरों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी निगम ने एक विशेष योजना चलाई है. इस योजना के तहत डॉक्टर, अभियंता, सनदी लेखाकार, लागत लेखाकार, कंपनी सचिव, वास्तुकार, वकील या कोई भी विकलांग व्यक्ति जिसने कोई पेशेवर/तकनीकी पाठ्यक्रम किया हो वह अपना उद्योग/कंपनी/कार्यालय आदि स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक के कर्ज़ के लिए आवेदन कर सकता है. यह ऋण भी 4 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध है.

एनएचएफडीसी ने विकलांग व्यक्तियों के हितों को देखते हुए पिछले साल अपनी गतिविधियों में विस्तार की पहल की थी. इसमें देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) जैसी अतिरिक्त चैनलाइजिंग एजेंसियां बनाना शामिल है. हमने अब तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और गुजरात के सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल किया है. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और असम के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं. इन बैंकों की ग्रामीण इलाकों में अच्छी तादाद है इसलिए ग्रामीण भारत में विकलांग व्यक्तियों को अपना काम-धंधा चलाने के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु ये सबसे उपयुक्त माध्यम हैं. इसके अतिरिक्त लाभार्थी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में एनएचएफडीसी की रियायती दरों पर ऋण प्राप्त करने के लिए गारंटी या ज़मानत आदि के तौर पर कोई चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भारत सरकार का ऋण गारंटी न्यास कोष, गारंटी देता है.

हालांकि 400 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हमारा यह एक लघु निगम है लेकिन विकलांग मामलों के विभाग के समर्थन से अपनी पूरी जिम्मेदारियों को समझते हुए हम हर विकलांग व्यक्ति जो अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है उसे सहयोग करने के लिए तैयार हैं. हम हर विकलांग व्यक्ति को आत्म-निर्भर बनाने के प्रति वचनबद्ध हैं और हमारा मकसद विकलांग व्यक्ति को सशक्त बनाना'' है.

एनएचएफडीसी. विकलांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण का माध्यम

के ज़रिए:

- सभी प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान.
- भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा चलने वाले व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र.
- भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए एनआईवीएच, एनआईएचएच, एनआईओएच, एनआईआरटीएआर, आईपीएच, एनआईएमएच जैसे राष्ट्रीय संस्थान.

के लिए:

- भारत सरकार द्वारा बढ़ईगीरी, मशीन वाइंडिंग, परिधान डिज़ाइनिंग, मोबाइल की मरम्मत आदि जैसे स्वीकृत सभी कौशल. (भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध)

प्रदान करता है:

- हर बार का प्रशिक्षण खर्च, अध्ययन सामग्री और टूल किट.
- प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान हर विद्यार्थी को 1,000 रुपए प्रति माह का स्टाइपैंड.

किसी भी विकलांग व्यक्ति का राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी), रेड क्रॉस भवन, सेक्टर 12, फरीदाबाद-121007 में स्वागत है. या वे 0129 . 2226910, 2287512, 2287513 फैक्स नंबर. 0129-2222339/2284371, ई-मेल nhfdc97@gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं.

(लेखक एनएचएफडीसी में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं)

रोज़गार समाचार

ईरा जोशी अतिरिक्त महानिदेशक
मारूफ आलम संपादक
अनुराग मिश्रा निदेशक
केपी मणिलाल लेखा अधिकारी
डॉ. ममता रानी संपादक
सूर्यकांत शर्मा व्यापार व्यवस्थापक
नलिनी रानी संपादक (विज्ञापन एवं संपादकीय)
विनोद कुमार मीणा संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
इरशाद अली संपादक (उर्दू)
पी.के. मंडल वरिष्ठ कलाकार

संपादकीय कार्यालय
रोज़गार समाचार
पूर्वी खण्ड IV
तल-5, रामकृष्णपुरम
नई दिल्ली-110066

ई-मेल : newsedit@gmail.com
ग्राम : 'Rozgar' New Delhi

संपादकीय : 26163055
विज्ञापन : 26104284
टेलीफैक्स : 26193012
वितरण : 26107405
टैलीफैक्स : 26175516
प्रोडक्शन : 26177529
लेखा (विज्ञापन) : 26193179
लेखा (वितरण) : 26182079

जलदीप वाला की ओर से रोज़गार समाचार को

महोदय/महोदया

मैं जलदीप वाला गुजरात का निवासी हूं. मैंने नाडियाद, गुजरात के डीडीयू से एमसीए किया है. मुझे आपका कॉलम 'हुनर से रोज़गार' बहुत पसंद है और मैंने इसके एक भाग में पढ़ा था कि सभी संगठनों ने हुनरमंद विकलांग व्यक्तियों को अपने यहां काम देना शुरू कर दिया है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है, मैंने विशेषज्ञ अधिकारी की परीक्षा उत्तीर्ण की है पर इसमें मेरा चयन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं एक 'विकलांग' हूं. यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी तीन बार 'विकलांगता' की वजह से मुझे सरकारी नौकरी का अवसर गवाना पड़ा है. मैं 75 प्रतिशत विकलांग हूं और मैं वॉकर के जरिए चल सकता हूं.

हर जगह सिर्फ यह उल्लेख ही होता है कि हम विकलांग व्यक्ति को समर्थन देते हैं पर वास्तव में वे ऐसा महान कार्य कभी नहीं करते. मैं अपने ज्ञान से देश की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन 'विकलांगता' के शाप के कारण ऐसा नहीं कर सकता. मैं इस कॉलम के लिए आपको फिर से धन्यवाद देता हूं.

उपर्युक्त कॉलम समाज के इस वर्ग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए रोज़गार समाचार की एक छोटी सी पहल है. बेहतर दिशा में यदि पूरी तरह नहीं तो कुछ बदलाव ज़रूर हो रहे हैं. इसमें सभी के सहयोग की ज़रूरत है. हमें यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि श्री जलदीप वाला वर्तमान में महुआ के श्रीमती के.बी.पारेख कॉलेज ऑफ कंप्यूटर सांइस में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं.

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए ईरा जोशी, अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटिंग प्रेस अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, सी-21 व 22, सेक्टर-59, नोएडा-201301 में मुद्रित, रोज़गार समाचार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ईस्ट ब्लाक-IV, लेवल-5, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 द्वारा प्रकाशित, संपादक-डॉ. ममता रानी